establish their supremacy in Goa, they saw to it that the existing cultural pattern was completely smashed? Now, Sir, I have some information that a huge amount of historical material in the Indian languages was transferred from here to Lisbon and it is still there in their archives. Will the Government of India, while negotiating with them, try to reclaim that because it concerns a very rich heritage which had come down to the Goan people over centuries?

SHRI BIPINPAL DAS: Sir, our Foreign Secretary, when he was in Lisbon recently, discussed this matter in detail and I hope we will come to some satisfactory settlement.

MR. CHAIRMAN: Very good. Yes, Mr. Swami.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, in pursuance of Mr. Goray's question, would the Minister inform this House, without there being a major national security leak, whether he would take up with the Portugal Government the question of giving compensation to all those who suffered during the Portuguese rule after 1947? In particular, many Members of Parliament today were in Portuguese jail for 2½ years and many in Goa lost property during the oppression of the Portuguese rule prior to the take-over by the present Government, prior to 1960. Would the Government take up the question of paying compensation to the affected people with the Portugal Government?

SHRI BIPINPAL DAS: This is a suggestion, and we will keep in mind.

SHRI SYED NIZAM-UD DIN: May I know from the hon. Minister whether before restoring diplomatic relations with the Portuguese Government, the Government of India will make it a condition that unless they agree to free all the African countries, restoration will not take place?

SHRI BIPINPAL DAS: As I said, the details are still under discussion.

इस्पात के मूल्यों पर से नियंत्रण का हटाया जाना

*641. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है;

(ख) सरकार इस्पात की वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार रखती है; और

(ग) क्या इस्पात के उत्पादन में हाल में कोई सुधार हुआ है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†[**Decontrol of steel prices**

*641. SHRI PRAKASH VIR SHASTRI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have considered the question of decontrolling the steel prices;

(b) what measures Government propose to take to improve the distribution system of steel; and

(c) whether there has recently been any improvement in the production of steel; if so, what are the details thereof?]

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस्पात के मूल्यों की घोषणा संयुक्त सयंत्र समिति द्वारा समय समय पर की जाती है। इस प्रणाली को बदलने का कोई विचार नहीं है।

(ख) वितरण प्रणाली की सतत समीक्षा की जाती है और जब और आवश्यक होता है

इसमें परिवर्तन किये जाते हैं। हाल में किये गये कुछ मुख्य परिवर्तन नीचे दिये गये हैं:—

(1) तिमाही आधार की बजाय इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात का आवंटन अब छमाही आधार पर किया जा रहा है।

(2) अप्रैल, 1975 से इस्पात प्राथमिकता समिति के लगभग 800 मुख्य आवंतियों को इस्पात कारखानों से सीधे प्रेषण किये जायेंगे; शेष उपभोक्ताओं को माल इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्ड की मार्फत दिया जायेगा।

(3) पुरानी प्रायोजनाओं की भावी मांगों तथा नई प्रायोजनाओं/स्वीकृत औद्योगिक इकाइयों की आवश्यक मांगों को देखते हुए सीधे आवंटितियों की सूची में समय-समय पर संशोधन किया जायेगा।

(4) संहत वर्ग के उद्योगों की सूची का विस्तार किया गया है और इसमें ड्रम, बैरल, कनस्तर, कसनियों और फर्नीचर के निर्माताओं को शामिल किया गया है। अप्रैल, 1975 से इस आधार पर सप्लाई की जायेगी।

(5) इस्पात सामग्री के लिए इण्डेंट बुक कराते समय बयाना जमा कराने की शर्त समाप्त कर दी गई है।

(ग) अप्रैल से नवम्बर, 1974 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के उत्पादन में 2,89,000 टन की वृद्धि हुई है।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The prices of steel are announced by the Joint Plan Committee from time to time. There is no proposal to change this system.

(b) The system of distribution is constantly under review and changes are made, as and when necessary. The following are some of the main changes made recently:—

(i) Allocation of steel by Steel Priority Committee is being made on a six-monthly basis instead of on a quarterly basis.

(ii) Despatches from the Main Steel Plants direct will be made from April, 1975 onwards to about 800 major SPC allottees; the remaining consumers would be provided steel by SPC through the stockyards of the main producers.

(iii) The list of direct allottees will be subject to revision from time to time in the light of future demands of old projects and essential demands of new projects/sanctioned industrial units.

(iv) The list of compact group of industries has been expanded by inclusion of manufacturers of drums, barrels and containers, fastners and furniture. Supplies will be made on this basis from Apail, 1975 onwards.

(v) Stipulation for deposit of earnest money while booking indents for steel materials has been dispensed with.

(c) There has been an increase to the extent of 2,89,000 tonnes in production of steel by the integrated steel plants during the period April to November, 1974, as compared to the corresponding period last year.]

†[ ] English translation.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, पहले मैं आपकी व्यवस्था यह चाहूंगा । कल भी यह बात उठी थी कि मूल प्रश्न हिन्दी में हो और मंत्री महोदय हिन्दी जानते हों तो चाहिए यह कि उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाये ।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी. . .

डा० लोकेश चन्द्र : मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, मैं स्वयं इस बात से सहमत हूं और माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम ने जो उत्तर भेजा है उसको वह हिन्दी में ही भेजा है ।

श्री नत्थी सिंह : यहां भी हिन्दी में बोलना चाहिए था ।

श्री चन्द्रजीत यादव : उत्तर मैंने हिन्दी में भेजा है । मैं अपने उत्तर को रिवाइज कर देता हूं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पहले ही हिन्दी में उत्तर देते तो सदन का दो मिनट का समय खराब नहीं होता । मैं इस बात के लिए संतोष व्यक्त करता हूं कि 1974 की अवधि में 2 लाख 79 हजार टन इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई, परन्तु मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश मे इस्पात का उत्पादन करने वाले जो कारखाने हैं उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और क्या ये सब कारखाने अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे हैं; यदि नहीं कर रहे तो कौन-कौन से कारखाने नही कर रहे और क्यों नहीं कर रहे ?

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन्, माननीय सदस्य को मालूम है कि सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य कारखाने हैं भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला—बोकारो का कारखाना अभी तैयार हो रहा है, वहां महज पिग-आइरन और इंगट बन रहे हैं । वह भी अपने लक्ष्य के मुताबिक बन रहा है । इसके अतिरिक्त एक दूसरा बड़ा कारखाना है इस्को, जिसमें सरकार के लगभग 35 प्रतिशत शेयर हैं । उसके अलावा—मैसूर स्टील आइरन है और इस्को है जिसका प्रबन्ध खद सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है । इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि ये कारखाने अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक लोहे का उत्पादन करें । जो इन कारखानों की इस्पात उत्पादन की क्षमता है उसका हम 80–85 प्रतिशत उत्पादन करना चाहते हैं । अभी इनका उत्पादन 70 प्रतिशत से भी कम है—विभिन्न कारखानों का विभिन्न प्रतिशत है । उदाहरण के लिए दुर्गापुर में उत्पादन बहुत ही गिरा था । उसके कई कारण हैं और वे इस सदन को बताये जा चुके हैं । मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस साल हम प्रयास कर रहे है कि आगे से हम इन कारखानों को उत्पादन क्षमता के मुताबिक इस्पात पैदा करने की कोशिश करें । जैसा मैंने कल भी कहा था इस सदन में, मुझे स्वयं इस बात से संतोष नही है कि जो लक्ष्य हम निर्धारित करें उतना ही पूरा करें । हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि जो हमारी उत्पादन की क्षमता है उसको अधिक से अधिक पूरा करें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : कन्ट्रोल और करप्शन का चोली-दामन का सम्बन्ध हो गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इस वर्ष देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ा है और विशेष रूप से जब से सीमेंट का अभाव हुआ है तब से लोगों की इस्पात खरीदने की सीमा स्वयं समाप्त हो गई है । क्योंकि मकान नहीं बन रहे हैं, इसलिए लोग इस्पात नहीं खरीद रहे हैं, तो ऐसी हालत में कन्ट्रोल जारी रखने का क्या उपयोगिता है ? क्या सरकार इसको शीघ्र समाप्त करने पर विचार कर रही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा है कि वस्तुत: सरकार का कोई वैधानिक रूप से मूल्य पर नियंत्रण नहीं है, यह काम जो हमारी संयुक्त कारखानों की समिति है वह समय समय पर देखती है कि कितनी कीमत उत्पादन की पड़ती है, कितना खर्चा उसको ले जाने में पड़ता है, बाजार में दूसरी वस्तुओं की क्या कीमत है, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए वह समिति कारखानों के स्तर पर कीमत निर्धारित करती है । लेकिन यह बात सही है कि सरकार भी मूल रूप से उस पर ध्यान रखती है इसलिए कि इस्पात किसी देश की मूल वस्तु होती है । यदि हम उसको बिलकुल एकदम से मुक्त कर दें, उस पर कोई नियंत्रण न रखें तो इसका असर ठीक नहीं पड़ेगा । लेकिन माननीय सदस्य को यह भी मालूम है कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर कोई नियंत्रण नहीं है । जो छोटे कारखाने बनाते हैं, जो आम जनता के इस्तेमाल की चीजें है, बार, राड या इमारत बनाने का सामान, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है । इसलिए विशेष रूप से कोई कठिनाई नहीं है । यह भी आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज की जो स्थिति है उसमें जो निर्धारित मूल्य कारखाने के स्तर का और जो बाजार में सामान लोहे का मिल रहा है उसमे करीब करीब फर्क समाप्त हो गया है । इसलिए कोई परेशानी, कोई कठिनाई इस समय नही है ।

SHRI V. B. RAJU: Sir, the hon. Minister has just said that the gap between the price fixed by the Joint Plant Committee and the price at which steel is available in the market is very much minimised. Can he kindly state whether it is because of the increased supplies or because of the declining demand or because of the raids that have taken place on the hoarders or because of the less developmental expenditure on construction? Which is the basic cause for this gap being reduced?

SHRI CHANDRAJIT YADAV: Sir, it will not be possible to identify only one reason. There are various factors responsible for this fall in the prices. The hon. Member may be knowing that the price of steel in the international market has also come down. Particularly in our country there are certain factors. One factor is that in comparison to last year. we have been able to pump in 9,22,000 tonnes of steel more this year. This is one factor, that we have supplied to the market 9,22,000 tonnes of more steel, both imported and indigenous steel. Number two, the Government has put certain restrictions on the construction of luxury buildings, multistoreyed buildings. And the developmental tempo of the country also is not so much. Because of the financial constraints, in our plan certain restrictions are there. The Government plan has also been reduced to some extent because of the financial constraints. So, the demand is not so much, the supply has improved and, therefore, the prices have come down.

SHRI KADERSHAH: The Minister has said that the production of steel during April-November, 1974 has increased. But the fullest capacity of the five integrated steel plants is stated to be 6.7 million tonnes. The target for last year was only 5.4 million tonnes, but the actual production was only 4.2 million tonnes. I do not know what the reason is for the low production. The Minister may give various reasons, but the obvious reason for it is that there is no co-ordination and no good planning. Crores of rupees of public money have been invested in these five integrated steel plants. I want to know how many of these steel plants are running in profit and how many are incurring loss. Also in view of the losses and in view of the fact that we have export opportunities, will the Government come forward to give importance to the Salem Steel Plant and the Vijayanagar Steel Plant?

SHRI CHANDRAJIT YADAV: Sir, many times I have explained in this House that we are not satisfied with the present rate of production. There were many factors for that and I do not want to enumerate all those factors here. But the Government is very carefully looking into those reasons which were responsible for low production. All necessary steps are taken. I myself called a meeting of the General Managers of all the steels plants this week. We have had detailed discussions. We have taken care to see that all those factors responsible for low production are removed. I can assure you that the production trend, at least this year, is very appreciable. We have been able to produce, in comparison to last year's eight months, more than 2,89,000 tonnes. So far as the Southern plants are concerned, only yesterday I said in this House that in regard to Salem steel plant, certain steps have already been taken. Administrative buildings are there. Certain engineering equipments have been ordered. And we are also taking care of whatever is required in this financial year. I am talking to the Finance Minister. We should take care to see that the work does not stop because of lack of finances. About the other two steel plants, I said yesterday, Sir, that we are commissioning the DPRs. I think, very soon the DPRs for two plants will be commissioned.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : चेयरमैन साहब, मैं यह जानना चाहती हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर के कारखाने हैं वे अपनी केपेसिटी का कितना प्रतिशत उत्पादन करते हैं ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहती हूं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर के कुल कितना उत्पादन करते हैं और हमें कितनी मात्रा में बाहर से इम्पोर्ट करके मंगाना पड़ता है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन्, प्राइवेट सेक्टर में एक टिस्को को छोड़ कर कोई बहुत बड़े कारखाने नहीं हैं । टिस्को में भी 35 प्रतिशत हिस्सा सरकार का है । दूसरे जो छोटे कारखाने प्राइवेट सेक्टर में हैं वे करीब 10 लाख टन लोहा हर साल पैदा करते हैं जिसको माइल्ड स्टील कहते है । हमारी आवश्यकता के लिए जो लोहा हमें बाहर से मंगाना पड़ता है उसका हम हर साल मूल्यांकन करते हैं कि हमें लोहे की कितनी आवश्यकता है । पिछला अनुभव हमारा यह रहा है कि छः से लेकर दस लाख टन लोहा हम विदेशों से आयात करते हैं । यह स्पेशियल किस्म का लोहा होता है । लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोहा हमें बाहर से आयात करना पड़ता है उसका उत्पादन इस देश में ही किया जाय ।

SHRI G. C. TOTU: Sir, in view of the fact that the prices of certain categories of steel like sheets, structural steel, etc. are still lower than the market rates and lower than the international prices, and in view of the further fact that 50 per cent of the material which is going into the private trade gets into black market even today, may I ask the hon. Minister as to why the Government does not increase the prices of these categories of steel so as to reduce blackmarketing?

SHRI CHANDRAJIT YADAV: Sir, as I have said earlier, the Government does not come into the picture in the fixation of the price. The price is fixed by the J.P.C. So far as the point that certain amount of steel goes into the black market is concerned, the hon. Member will be knowing that certain effective steps have been taken during the last few years. We have given instructions to our Regional Steel Controllers that they should take full care, they should see that bogus firms are not in existence, they should see that blackmarketting does not take place. and they should see that hoarding is not allowed. And certain raids have taken place dur-

ing the last few months and those people who have been dealing in black market, etc. have been brought to book. I can assure the hon. Member that even today, I have called for a meeting of the Regional Steel Controllers. We are going to take certain effective steps so that this kind of corruption and blackmarketing do not exist in the matter of steel.

Reimbursement of Expenditure incurred on Pakistan POWs

*642. B. S. SHEKHAWAT:†
SHRI B. K. SAKHLECHA:
DR. RAMKRIPAL SINHA:
SHRI D. K. PATEL:
SHRI K. N. DHULAP:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state the progress made on the question of reimbursement by Pakistan of the amount paid as advance of pay to Pakistani prisoners of War repatriated to Pakistan?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS): The pay and allowances disbursed to the Pakistani Prisoners of War and Civilians under Protective Custody amounted to Rs. 3,69,55,000/-. The question of reimbursement of this amount was taken up with the Government of Pakistan through a note dated September 29, 1973. This matter was also taken up in April, 1974 during the visit of the Pakistan Minister of State for Defence and Foreign Affairs The last communication in this regard was sent to the Government of Pakistan on November 2, 1974. While the Government of Pakistan have promised to examine the matter, they have so far not sent their final views on the subject.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri B. S. Shekhawat.

श्री भैरों सिंह शेखावत : क्या यह सही है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत सरकार का तमाम बकाया है और उस बकाए में वार प्रिज़नर्स को जो अलाउंसेज दिए हैं वे भी शामिल हैं ? तो क्या शिमला समझौते के समय और शिमला समझौते के बाद भारत-पाक के बीच में जितनी वार्ताएं हुई क्या उन वार्ताओं में इस अलाऊंस के प्रश्न को और बाकी और बकाया के भुगतान के प्रश्न को भारत सरकार की ओर से उठाया गया और यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया थी ?

SHRI BIPINPAL DAS: Sir, the question asked was only about reimbursement by Pakistan of the amount paid in advance to Pakistani prisoners who were under detention and I do not understand the hon. Member bringing in other questions.

श्री भैरों सिंह शेखावत : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर तो बता दीजिए । शिमला समझौते के समय और उसके बाद भारत सरकार ने प्रिज़नर्स के अलाऊंस वगैरह के संबध में जो क्लेम किया है उसकी वसूली के संबध में कब कब प्रश्न उठाया गया और आज तक पाकिस्तान उसका भुगतान क्यों नहीं कर सका ? पाकिस्तान इसका क्या कारण दे रहा है ?

SHRI BIPINPALL DAS: Sir, I have already answered in the main answer that we took up this question on the 29th of September, 1973.

MR. CHAIRMAN: Three times.

SHRI BIPINPAL DAS: Four times up till now.

SHRI SARDAR AMJAD ALI: Sir, the question is, after having the Simla Agreement and also thereafter when all the deliberations took place between our team and the Pakistani